दलहनों का उत्पादन

1514. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत में देश में दलहनों के उत्पादन के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए दलहन के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्रत्येक वर्ष के दौरान दलहनों का वास्तविक उत्पादन कितना-कितना हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी मिशनों की स्थापना की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इन मिशनों द्वारा विकसित की गई तकनीक को व्यवहार में लाकर देश के किस-किस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने हेतु उपयोग किया गया था और इसके फलस्वरूप उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) उत्पादन लक्ष्य हमेशा अधिक रखा जाता है । यही कारण है कि गत वर्षों में इसे प्राप्त नहीं किया जा सका है, सिवाय 1989-90 के, जब 13.30 मिलियन मीटरी टन के लक्ष्य की तुलना में 13.85 मिलियन मीटरी टन उत्पादन हुआ था ।

(ख) 1991-92 से 1993-94 की अवधि के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं—

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन मीटरी टन)	उपलब्धि (मिलियन मीटरी टन)
1991-92	15.50	12.02
1992-93	14.50	13.60
1993-94	15.55	14.21

(ग) एवं (घ) तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में की गई थी और बाद में 1990 में इस मिशन में दलहन को भी शामिल कर दिया गया था । मिशन द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली के परिणामस्वरूप 1986-87 की तुलना में 1993-94 के दौरान तिलहन का उत्पादन आन्ध्र प्रदेश (102%), हरियाणा (223%), कर्नाटक (44%), मध्य प्रदेश (262%), महाराष्ट्र (160%), राजस्थान (225%), तमिलनाडु (47%) उत्तर प्रदेश (47%) तथा पश्चिम बंगाल (90%) में बढ़ा है । तथापि, दलहन उत्पादन में अभी वांछित वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकी है ।

मत्स्य उत्पादन

1515. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 6,000 कि. मी. समुद्री तट है जिसकी प्रति वर्ष 3.9 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन की क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मत्स्य-उत्पादन की क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो औसत वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मत्स्य नीति अपनाने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस नीति के अधीन किन-किन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) समुद्री मात्स्यिकी क्षमता लगभग 3.92 मिलियन मी. टन आंकी गई है जिसमें 2.28 मिलियन मी. टन, 0—50 मीटर गहराई से 1.37 मिलियन मी. टन 50—200 मीटर गहराई से 0.30 मिलियन मी. टन 200—500 मीटर से गहराई से और 0.24 मिलियन मी. टन समुद्री क्षेत्र से शामिल है । मत्स्य बेड़े की उपलब्ध क्षमता और बुनियादी सुविधाओं से फिलहाल समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का दोहन लगभग 69 प्रतिशत के स्तर तक किया जा रहा है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री संसाधनों से वार्षिक मत्स्य उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1991-92	2.45 मिलियन मी० टन
1992-93	2.58 " "
1993-94	2.69 " "

(घ) तथा (ङ) विद्यमान नीति के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य मात्स्यिकी का विकास करना है जिसके पार्श्व मछुवारों मत्स्या किसान तथा मत्स्य उद्योग के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने, पारम्परिक मछुवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, तटवर्ती और ग्रामिण गरीबों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने, मात्स्यिकी संसाधनों का संरक्षण व प्रर्वधन, तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य निहित हैं ।

जहां तक समुद्री मात्स्यिकी का संबंध है, सरकार निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, अर्थात् पारम्परिक नौकाओं का मोटरीकरण; प्लाईवुड नौकाओं को प्रारम्भ करना; समुद्र तट से दूर गहरे पानी में मछली पकड़ने हेतु इन्टरमीडियट नौकाएं शुरू करना ; 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मत्स्य यानों द्वारा प्रयोग किये गए हाई स्पीड डीजल आयल पर केन्द्रीय उपाद्द शुल्क की प्रतिपूर्ती करना ; प्रमुख तथा लघु पत्तनों पर अवतरण तथा जहाजों को गोदी लगाने की सुविधाएं सृजित करना; तथा संसाधन के क्षमतानुसार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समुद्र में कृत्रिम चट्टानों का निर्माण एवं समुद्र में मछली पकड़ना ।

Shortage of Milk and Milk Products in Madhya Pradesh

1516. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to - state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of Milk products particularly butter in the country and especially in the State of Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government propose to take to increase the production of milk in the Loiintry particularly fa Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SS KRISHANA KUMAR) : (a) and (b) There was shortage of milk, butter and ghee in the country during the months of August, September and October, 1994. In Madhya Pradesh there was some shortage of ghee but not of milk or butter.

(c) The shortages have eased including in Madhya Pradesh. Government does not apprehend any shortages of these consumables in ihe near future.

Survey of Poultry Farms in Madhya Pradesh

1517. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(i) whether i i at have conducted any survey about the existing poultry farms in the State of Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the district-wise details thereof;

(c) whether Government are aware of the difficulties being faced by the poultry farmers in the States;

(d) if so, what are the details thereof and what action Government have initiated to remove those difficulties; and

(e) what steps Government propose to take to develop poultry farming in Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OFAGRICULTURE [SHRI S. KRISHNA KUMAR) (a) No. Sir.

(hi) Does not arise.

(c) to (e) Government are aware of the difficulties faced by poultry farmers. The major constraints faced by poultry farmers relate to marketing support, access to health care support, aw liability of quality feeds etc. Central and State Governments have taken up various poultry development programme to ensure provision of inputs like quality chicks and poultry feed at reasonable prices, disease control measures etc.

Cotton Production in Non-Traditional Areas

1518. SHRI T. VENKATRAM REDDY : Will the Minister of AGRICULTURE be